

बीएसईएस उपभोक्ताओं ने घरों में लगाए 56 लाख एलईडी बल्ब्स होगी 124 मिलियन यूनिट बिजली की बचत

नई दिल्ली: 24 जनवरी, 2017। बीएसईएस ने ईईएसएल यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर अपने उपभोक्ताओं को काफी कम कीमतों पर 56 लाख से अधिक एलईडी बल्ब्स उपलब्ध कराए हैं। बीआरपीएल उपभोक्ताओं ने लगभग 37 एलईडी बल्ब खरीदे, जबकि बीवाईपीएल उपभोक्ताओं ने करीब 20 लाख एलईडी बल्ब खरीदे। इन 56 लाख एलईडी बल्बों से बीएसईएस क्षेत्रों में 124 मिलियन यूनिट बिजली की बचत होगी।

बीआरपीएल के जिन डिविजनों के उपभोक्ताओं ने सर्वाधिक एलईडी बल्ब्स खरीदे गए, वे हैं— नेहरू प्लेस, अलकनंदा, साकेत, नजफगढ़, टैगोर गार्डन और जनकपुरी। वहीं, बीवाईपीएल के जिन डिविजनों के उपभोक्ताओं ने सबसे ज्यादा एलईडी बल्ब्स खरीदे हैं, वे हैं— लक्ष्मी नगर, कड़कड़डूमा, कृष्णा नगर, यमुन विहार, जीटी रोड और पटेल नगर। एलईडी बल्ब की यह स्कीम 1 जून, 2015 को बीएसईएस उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई थी।

क्या है स्कीम:

इस स्कीम के तहत एक उपभोक्ता 9 वॉट का एक एलईडी बल्ब अपेक्षाकृत काफी कम कीमतों पर यानी 65 रुपये में खरीद सकते हैं। हर एलईडी बल्ब पर निर्माता की ओर से तीन साल की वॉरंटी भी दी जा रही है।

एलईडी के फायदे

एलईडी बल्ब्स के इस्तेमाल से न सिर्फ ऊर्जा का संरक्षण होता है, बल्कि बिजली बिल के रूप में बड़े पैमाने पर आर्थिक बचत भी होती है। 7 वॉट एक एक एलईडी बल्ब उतनी ही रोशनी देने वाले सीएफएल के मुकाबले 50 प्रतिशत कम बिजली की खपत करता है और उतनी ही रोशनी देने वाले पारंपरिक बल्ब के मुकाबले 85 प्रतिशत कम बिजली की खपत करता है।

उपभोक्ताओं द्वारा 57 लाख एलईडी बल्ब्स खरीदे जाने पर बीएसईएस प्रवक्ता ने कहा — जैसा कि एलईडी की कीमतें गिर रही हैं, ऐसे में, इनमें ऊर्जा संरक्षण की अपार संभावनाएं हैं, और साथ ही ये जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। सामाजिक प्रतिबद्धताओं से लैसे युटिलिटी होने के नाते, बीएसईएस हमेशा ही ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देती रही है। हम एलईडी और सौर नेट मीटरिंग जैसी टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी तकनीकों को काफी प्राप्साहन दे रहे हैं। बीएसईएस आगे भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट लाइटिंग के विकल्पों के बारे में जागरूक करती रहेगी।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।
